1	2	3	4
2.	मैसर्स इंडो-जर्मन फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई और उनके वितरक नामश : मैसर्स जय श्री हाउस, रांची।	अखिल भारतीय उपभोक्ता परिषद, बिहार ने आज पटना में दिनांक 1-12-1984 को और रांची एक्सप्रेस में 29-12-84 को कम्पनी द्वारा निर्मित इनर्जी फोर्ट के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञापन की ओर आयोग का ध्यान दिलाया।	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारि व्यवहार आयोग ने महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) द्वारा जांच सम्पन्न करने का आदेश दिया । आगे कार्यवाही जांच रिपोर्ट प्राप्त करने पर आयोग द्वारा की जायेगी ।
3.	मैसर्स अमृतांजन लिमिटेड, मद्रास	एक विज्ञापन "टाइम्स आफ इंडिया" दिनांक 11-9-1985 को अमृतांजन "मार्क दी लैण्ड मार्क" प्रतियोगिता के सम्बन्ध में प्रकाशित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की सूचना में आया।	आयोग ने जांच का आदेश दिया है। इसी बीच उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद ने कम्पनी के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश स्वीकृत करने के आवेदन सहित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 36ख (क) के अन्तर्गत आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है । अन्तरिम व्यादेश के लिए आवेदन की सुनवाई के लिए 29-11-1985 निश्चित की गई है ।

Public Sector Undertakings without Heads of Management

926. SHRI B. KRISHNA MOHAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of Public Sector Undertakings without Heads of management at present; and

(b) what are the reasons for the dealy in making appointments thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) According to available information out of 210 Central Public enterprises, 38 posts of Chief Executives are vacant at present. The Public Enterprises Selection Board (PESB) have already made their recommendations in respect of 26 posts and the Government have given their approval in respect of four posts.

(b) The recommendations of the PESB are processed by the administrative Ministry/Department concerned and appointments are made only with the approval of the Appointments Committee of the Cabinet. Delays occur where persons selected take time or fail to join; or in cases where persons with specialised skills have to be spotted.

Taking up of power projects by private sector

927. SHRIMATI USHA MALHOTRA:

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV:

SHRI J. P. GOYAL:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided that power projects outside the 7th Five Year Plan